POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, मी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जनवरी, 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

पिछले महीने दस दिसम्बर को राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में राज्य सरकार द्वारा पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 मनाया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका को बढ़ावा देना और राज्य में निवेश को आकर्षित करना था।

देश-विदेश के प्रवासियों, कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख उद्योगपतियों और हस्तियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, जो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 'विकसित भारत 2047' में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थानी पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने वादों को निभाते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी देश-दुनिया में राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हर साल 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की भी घोषणा की।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान में निवेश की जरूरत के साथ अपार संभावनाएं भी मौजूद है...निवेश के लिए प्रदेश में नई-नई राहें भी खुली हैं। क्योंकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में राजस्थान सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधारों की ओर बढ़ रहा है। जरूरत यह है कि हमारी निवेश नीति में सरलता-पारदर्शिता और जवाबदेहिता पर खास ध्यान दिया जाए, साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाया जाए।

> 'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

बदलाव का कदम...श्रम क्षेत्र में बड़ा सुधार... नया लेबर कोड लागू

केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नई श्रम संहिता (लेबर कोड) को लागू कर दिया है। इससे निजी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगार लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते का नारा देते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इससे विकसित भारत की यात्रा को तेज गति मिलेगी। लेबर कोड में अनिवार्य नियुक्ति पत्र, न्यूनतम और समय पर वेतन की गारंटी और एक साल में ही ग्रेच्युटी भुगतान की व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ईएसआइसी सुविधा और 40 साल की सेवा के बाद अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने नया लेबर कोड लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, पीएम मोदी द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। इससे करीब 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए खास सुविधाएं जोड़ी गई है।

ऑपरेशन में आंख की रोशनी गई, अस्पताल को देना होगा मुआवजा

सीकर जिले के गांव जोगियों का बास निवासी श्रीराम ने जिला उपभोक्ता आयोग, झुंझुनूं में सेठ आनंदराम जयपुरिया नेत्र अस्पताल, स्टेशन रोड, नवलगढ़ और चिकित्सक डॉ.ईसरत सदानी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी श्रीराम ने वर्ष 2012 में उक्त नेत्र अस्पताल में उपचार कराया था। ऑपरेशन के बाद उनकी आंख में तेज दर्द, सूजन और दिखाई देने में परेशानी बनी रही। अस्पताल में लंबे इलाज के बावजूद सुधार नहीं हुआ और आंख की रोशनी चली गई। जब परिवादी ने जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में जांच कराई तो चिकित्सकों ने बताया कि आंख में लेंस गलत तरह लगाया है।

उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई पर अस्पताल की ओर से अनुभवी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करने, मरीज के आंख मसलने, समय पर दवा नहीं लेने के कारण आंख की रोशनी जाने जैसी कई दलीलें दी गई। आयोग ने दस्तावेजों के आधार पर दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने इसे 'सेवादोष' और चिकित्सीय लापवाही मानते हुए उक्त नेत्र अस्पताल एवं चिकित्सक को संयुक्त रूप से 6 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा मय 6 फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।

देश में बन रहे हैं अब एआई विलेज

भारतीय कृषि में अब एआई के जरिए एक नई क्रांति आ रही है। एआई और मशीन लर्निंग अब उपग्रहों, ड्रोन और जमीन में लगे छोटे-छोटे सेंसर्स से हर पल लाखों डेटा पॉइंट जुटा रहे हैं। ये डेटा ही बताते हैं कि मिट्टी के किस कोने में कितने पानी की जरूरत है, हवा में कौन सी बीमारी का खतरा है, खेत में कितनी व कौनसी खाद या कीटनाशक जरूरी है...।

हाल ही 15 कंपनियों ने मिलकर एआई मॉडल विलेज की अवधारणा को पेश किया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सतनवरी गांव में चल रहा है। यह पहला एआई विलेज है। यहां खेती से लेकर हर काम एआई से हो रहा है। प्रोजेक्ट के नतीजे काफी उत्साहजनक है। इससे 50 फीसदी पानी बचा, खाद व कीटनाशक 40 फीसदी घटा और पैदावार 50 से 70 फीसदी बढ़ी है...।

युवाओं का स्वरोजगार पर भरोसा बढ़ा

देश में अब युवाओं का रुझान नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार पर है। जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। पिछले छह वर्षों में जितना रोजगार सृजन हुआ, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्वरोजगार का रहा है।

हाल ही जारी एचएसबीसी की 'एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 में स्वरोजगार 23.9 करोड़ था जो बढ़कर 2024 में 35.8 करोड़ हो गया है। स्वरोजगार में वृद्धि श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि के साथ-साथ हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2018 में 53 फीसदी से बढ़कर 2024 में 64.3 फीसदी हो गई। 2024 में कुल रोजगार में 15.5 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें 58.2% पुरुषों की तथा 31.7% महिलाओं की भागीदारी रही। महिला रोजगार 10.3 करोड़ बढ़ा, जो पुरुषों से लगभग दोगुना है।

घटिया बीज दिया तो लगेगा जुर्माना

देश में किसानों को घटिया बीज देने पर अब कंपनी व विक्रेता पर मोटा जुर्माना लगेगा। साथ ही बीज काम में लेने के बाद फसल का प्रदर्शन कमजोर रहने पर किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा भी मिलेगा।

केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित नए बीज विधेयक-2025 के ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है। इसमें किसानों के अधिकारों की रक्षा एवं गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। नए विधेयक के ड्राफ्ट में बाजार में गुणवत्ता वाले सस्ते बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नकली व घटिया बीजों की बिक्री रोकना तथा बीज आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही लाने जैसे प्रस्ताव शामिल है।

मोबाइल पर मिलेगा हेल्थ रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में हर नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और डिजीटल स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रदेश में हर आदमी का हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर मिल सकेगा। सरकार ने 100 प्रतिशत लोगों के आभा कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। प्रदेश में सभी ओपीडी एवं आईपीडी में मरीज की आभा आईडी बनाई जाएगी।

निवेशकों को मिलेगी हर संभव मदद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेशकों को निवेश के लिए हर संभव मदद की जाए। साथ ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से उनके निवेश प्रस्तावों पर जरूरी कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की प्रगति में बड़े साझेदार बने हैं। हमारी प्राथमिकता है कि प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मिट्टी से जुड़ाव बना रहे। प्रवासियों के कल्याण तथा उनके हितों के लिए 'राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग' का गठन किया गया है। सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की घोषणा की है। जिससे इन चैप्टर्स की कुल संख्या अब बढ़कर 40 हो गई है।

सरकारी स्कूलों की होगी मॉनिटरिंग

राजस्थान में अब एक स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण का गठन होगा। इसके जरिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग, विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के प्रयास होंगे। प्राधिकरण एक लाख से अधिक स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगा।

नई शिक्षा नीति में इस प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं शिक्षकों की योग्यता, स्कूलों की सुरक्षा सहित गई अन्य मुद्दों की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर अहम कदम उठाए जाएंगे। इससे ग्रामीण स्तर तक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ अनेक सुविधाएं मिलेंगी।

किसान सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों को 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और प्रदेश 3 हजार रुपए अपनी हिस्सेदारी के रूप में दे रहा है। अब राजस्थान अपनी हिस्सेदारी में 3 हजार रुपए और बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही की गई घोषणा के अनुसार अब जल्द ही राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर 6 हजार रुपए हो जाएगी। इसके बाद लाभार्थी किसानों को साल में तीन किश्तों में 12 हजार रुपए मिलेंगे। इससे प्रदेश के 76 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा।

प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा होगा मजबूत

राजस्थान सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2030 और 2047 में प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। विजन का मतलब होता है कि हमे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जो लक्ष्य रखे गए हैं, वे निश्चित रूप से पूरे होंगे।

इसमें हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), हर मेडिकल कॉलेज में इंटीग्रेटेड मेडिकल एजूकेशन हब बनाने, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को मौजूदा दर की तुलना में 10 प्रतिशत तक लाने जैसे कई बड़े लक्ष्य शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को इन बड़ी उम्मीदों को पूरा करने के लिए लम्बी छलांग लगानी होगी।

देश में स्पष्ट इरादे से हो रहे हैं सुधार

'कोई भी कानून किसी नागरिक पर बोझ नहीं होना चाहिए। नियम-कानून हमेशा लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए। देश पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' चरण में है, जहां सुधार तेजी से, स्पष्ट इरादे से हो रहे हैं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें एनडीए संसदीय दल की बैठक में कही। उन्होंने कहा, सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं। इनका लक्ष्य लोगों की रोज की बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने एनडीए सांसदों से आम लोगों की असल समस्याओं को सक्रिय रूप से शेयर करने का आग्रह किया ताकि रिफॉर्म एक्सप्रेस हर घर तक पहुंच सके और रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर कर सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें नागरिकों के दरवाजे पर सेवाएं देनी हैं।

प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी

पंचायती राज विभाग से अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान में पंचायतों का नक्शा फिर से बदल गया है। प्रदेश के 41 जिलों में 3441 नई पंचायतें जोड़ी गई हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 14500 हो गई है। अब करीब 3400 सरपंच ज्यादा चुने जाएंगे।

पंचायत समिति और जिला परिषदों की संख्या में बढ़ोतरी होने से अब कई बदलाव दिखाई देंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों में गति आई है। सरकार परिसीमन के बाद नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचना एवं प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने में लगी है। वार्ड बढ़ने से करीब डेढ़ लाख प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। चुनावों में बड़ी संख्या में युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखने को मिलेगी।

स्टार्टअप को मिलेगी नई दिशा

राजस्थान एक ऐसे ग्लोबल आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जो प्रदेश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम को नई दिशा दे सकता है। डीजी फेस्ट एवं टाई ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में होगा। दुनियां के 30 देशों से उद्यमी निवेशक, इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी जगत से जुड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे।

समिट में दुनियाभर के स्टार्टअप, करीब 10 हजार उद्योगपति, 500 से ज्यादा निवेशक और 100 से अधिक वक्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राजस्थान को ग्लोबल इनोवेशन और स्टार्टअप मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। भविष्य में निवेश और अद्योगों के लिए नये आयाम खुलेंगे। समिट के दौरान राज्य सरकार अपनी नई एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पॉलिसी भी लान्च करने की तैयारी कर रही है।

बजट में मिलेंगी 20 वर्ष आगे की इबारत

प्रदेश के इस बार के बजट में विकसित राजस्थान @2047 विजन में शामिल आर्थिक विकास, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा और शासन सुधार की राह में पहला कदम होगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि यह मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और पहली चुनौती है। यह विजन उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और कई विभागों ने इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। यह भी तय है कि विकसित राजस्थान लक्ष्यों की निगरानी व कार्य में तेजी लाने के लिए एआइ व मशीन लर्निंग टूल्स का भी सहारा लिया जाएगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कल्प' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485